

सोलर परियोजनाओं में लगेंगे सिर्फ भारत निर्मित सेल

जगरण ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक अहम कदम उठाया है। जून, 2026 के बाद देश में लगने वाली किसी भी (सरकारी या निजी) सोलर परियोजना में सिर्फ भारत में उत्पादित सोलर माड्यूल्स या सोलर सेल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अप्रूव्ड माड्यूल्स एंड मैनुफैक्चरर्स आफ सोलर फोटोवोल्टिक आर्डर (एएलएमएम-2019) में अनिवार्य संशोधन कर आवश्यक प्रविधान किए हैं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि यह संशोधन भारतीय सौर ऊर्जा सेक्टर के लिए और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। इसमें एएलएमएम फ्रेमवर्क के तहत सोलर टीवी सेल्स मैनुफैक्चरिंग कंपनियों की बहुप्रतीक्षित सूची है। इस सूची में

- जून, 2026 से लागू होगा यह नियम, वर्ष 2019 की नीति में किया गया संशोधन
- भारत की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की कुल क्षमता अभी 94 हजार मेगावाट



13,200 मेगावाट क्षमता के माड्यूल्स का आयात

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत ने 13,200 मेगावाट क्षमता के सोलर माड्यूल्स का आयात किया है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 338 प्रतिशत ज्यादा है। जबकि इसी दौरान सोलर सेल के आयात में 155 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में भारत ने 51,460 करोड़ रुपये के सोलर सेल का आयात किया था और इसमें से तकरीबन 90 प्रतिशत चीन से आया था। चीन से आयातित सोलर सेल पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने के बावजूद उनका आयात नहीं थम रहा है। भारत की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की कुल क्षमता अभी 94 हजार मेगावाट है। वर्ष 2030 तक इस क्षमता को तीन लाख मेगावाट करने का लक्ष्य है। आर्थिक शोध एजेंसी जीटीआरआइ का कहना है कि वर्ष 2030 तक भारत को 30 अरब डालर का सोलर सेल आयात करना पड़ सकता है।

शामिल कंपनियों से ही जून, 2026 के बाद सोलर माड्यूल्स व सेल की आपूर्ति की जाएगी।

सरकार की तरफ से बताया गया है कि सरकार की समर्थित परियोजनाओं, नेट मीटरिंग

प्रोजेक्ट्स और ओपेन एक्सेस वाली नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजनाओं के लिए इस सूची में शामिल कंपनियों से ही सौर ऊर्जा उपकरणों की खरीद करनी होगी। सरकार अभी तक इस सूची को इसलिए जारी नहीं

कर रही थी कि देश में सोलर सेल बनाने वाली कंपनियों की संख्या बहुत कम थी और यह बात भी पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती थी कि वह घरेलू परियोजनाओं की मांग को पूरा कर सकेंगी या नहीं।